# 7 जुलाई

# संसदीय समितियों के कार्यकाल विस्तार की संस्तुति

| यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित | |
|---|---|
| **प्रारम्भिक परीक्षा** | **मुख्य परीक्षा** |
| **प्रथम प्रश्न पत्र :** राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ | **द्वितीय प्रश्न पत्र :** संसदीय समितियां |

## संदर्भ

- हाल ही में, राज्यसभा सचिवालय के क्रियाकलापों में प्रणालीगत सुधार का सुझाव देने के लिए इस वर्ष जनवरी में गठित एक समिति ने सभापति एम वेंकैया नायडू से स्थिरता और निरंतरता के लिए सदन के पैनल के कार्यकाल को दो वर्ष विस्तारित करने की संस्तुति की है।

## विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

## पृष्ठभूमि

- पैनल की स्थापना इस वर्ष जनवरी में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने की थी।
- राज्यसभा सचिवालय के कामकाज और अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों का अध्ययन करने वाली विस्तृत रिपोर्ट में 130 सिफारिशें की गई हैं।
- ध्यातव्य है कि 2020 में कोविड -19 महामारी की शुरुआत के बाद से सदन के पैनल की बैठकें लगभग दो वर्षों से स्थगित थीं।

## संस्तुतियाँ

- श्री रामाचार्युलु समिति ने सुझाव दिया कि संसदीय समितियों का कार्यकाल वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किया जाना चाहिए।

- विदित है कि व्यापक विस्तार के लिए रिपोर्टों पर विमर्श करने हेतु संसद में प्रस्तुत किया गया। इसने उद्योग और वाणिज्य पर दो मौजूदा समितियों को एक में विलय करने और पर्यटन और संस्कृति पर एक नई समिति स्थापित करने की भी सिफारिश की।
- उनके क्षेत्र दौरे के संदर्भ में कहा गया है कि उनकी वर्तमान दो यात्राएं, जो एक वर्ष में अधिकतम दस दिवसीय है, को पंद्रह दिवसीय तीन यात्राओं में संशोधित किया जाना चाहिए।
- डीआरएससी द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के प्रयासों और उनके आयात और निहितार्थों के दृष्टिगत रिपोर्ट की सामग्री के व्यापक प्रवर्धन के लिए संसद में चुनिंदा प्रमुख रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए एक समिति समय की सिफारिश की गई है।
- राज्यसभा सचिवालय की समिति अनुभाग में सभी रिक्तियों को भरे जाने की संस्तुति की गई। वर्तमान में, राज्यसभा की आठ विभाग संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs) 27% से 40% से अधिक कर्मचारियों की कमी के साथ कार्य कर रही हैं।
- हाउस पैनल के सदस्यों को लिखित रूप में समिति की रिपोर्ट को अपनाने के लिए अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने की अनुमति दी जाए।
- समिति ने सिफारिश की है कि इन रिपोर्टों को हितधारकों और आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए।

**राज्यसभा सचिवालय की वर्तमान स्थिति**

- यह राज्यसभा सचिवालय का अब तक का पहला व्यापक अध्ययन है।
- अध्ययन ने सचिवालय के काम को सुव्यवस्थित करने का सुझाव दिया है, जिसमें वर्तमान में सचिवालय में मौजूद दस-परत पदानुक्रम में निचले और मध्यम स्तर के 75% मुद्दों का निदान शामिल है।
- राज्यसभा सचिवालय की शुरुआत 1952 में 200 अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हुई थी।
- वर्तमान में इसमें 1,700 कर्मचारी हैं।

**संसदीय समिति**

- संसदीय समिति को उस समिति के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के

निदेशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

| संसदीय समितियां के प्रकार | |
|---|---|
| **स्थायी समितियां** | **तदर्थ समितियां** |
| ▪ स्थायी समितियां, स्थायी एवं नियमित समितियां हैं, जिनका गठन समय-समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है।<br>▪ इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है।<br>▪ उदाहरण- वित्तीय समितियां, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (डीआरएससी) तथा कुछ अन्य समितियां स्थायी समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। | ▪ तदर्थ समितियां, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं और जब वे अपना काम समाप्त कर लेती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं, तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।<br>▪ उदाहरण- प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों संबंधी प्रवर तथा संयुक्त समितियां।<br>▪ रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति इत्यादि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। |
| **सामान्यतः संसदीय समितियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है** | |
| 1. | वित्तीय समितियां |
| 2. | विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां |
| 3. | अन्य संसदीय स्थायी समितियां |
| 4. | तदर्थ समितियां |

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

# क्षय रोग के रिवर्स जूनोसिस संक्रमण के प्रसार के साक्ष्यों की पुष्टि

| यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित | |
|---|---|
| **प्रारम्भिक परीक्षा** | **मुख्य परीक्षा** |
| **प्रथम प्रश्न पत्र :** राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ | **तृतीय प्रश्न पत्र :** रोग |

**संदर्भ**

- नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और तमिलनाडु के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान (एनआईआरटी) के शोधकर्ताओं ने टीबी प्रसार में रिवर्स जूनोसिस अर्थात मानव से पशु और पशु से मानव में संक्रमण के प्रसार के साक्ष्यों की पुष्टि की है।

**विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु**

- भारत ने 2019 में 2.4 मिलियन से अधिक टीबी मामलों की सूचना दी, जो वैश्विक टीबी बोझ का सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है।
- वर्ष 2012 में गत जनगणना की तुलना में 4.6% की वृद्धि के साथ, देश का कुल पशुधन 535.78 मिलियन है।
- एक नए अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी बैक्टीरिया (मानव से पशु और पशु से मानव) के संचरण का अध्ययन करने का प्रस्ताव है। इसके लिए टीबी संक्रमण के लिए पशुओं की नियमित जांच की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। साथ ही, संक्रमित जानवरों को समूह से अलग किए जाने का प्रस्ताव रखा गया।
- संस्थान 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में बीसीजी प्रत्यावर्तन के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।

**मानव-पशु संचरण**

- टीबी रोगियों से एरोसोल उत्पन्न होते हैं, जिनके माध्यम से इसका संचरण होता है।

- टीबी रोगी जब खांसते अथवा छींकते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में एरोसोल उत्पन्न होते हैं, जो जानवरों सहित विभिन्न जीवों के लिए जोखिम का स्रोत बनते हैं।
- जब मवेशी या कोई अन्य घरेलू जानवर इन एरोसोल के संपर्क में होते हैं, तो उनके संक्रमित होने की अधिक संभावना होती है। साथ ही, जानवरों से यह संक्रमण इंसानों में पहुंच सकता है।

**तपेदिक या टीबी**

- तपेदिक या टीबी सामान्य तौर पर एमटीबी जीवाणु (माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस) के कारण होता है और इसका क्रमशः प्रसार होता है।
- विश्व की लगभग एक-चौथाई आबादी के टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित होने का अनुमान है।
- एक अनुमान के अनुसार, टीबी से हर साल 13 लाख मौतें होती हैं। इनमें से केवल 5-15 फीसदी लोग सक्रिय टीबी रोग से बीमार पड़ते हैं। बाकी को टीबी का संक्रमण है लेकिन वे बीमार नहीं हैं और बीमारी को फैला नहीं सकते हैं।

**प्रभावित देश**

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, टीबी से प्रभावित होने वाले अधिकांश लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, किन्तु टीबी पूरी दुनिया में मौजूद है।
- टीबी से पीड़ित आधे से अधिक लोग 8 देशों में पाए जा सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

**भारत टीबी रिपोर्ट 2022**

- भारत में गत वर्ष की तुलना में 2021 में तपेदिक के मामलों में 19 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की गई।
- 2021 के दौरान अधिसूचित टीबी रोगियों (नए और रिलैप्स) की कुल संख्या 19, 33,381 थी, जबकि 2020 में यह 16, 28,161 थी।
- भारत में 2019 से 2020 के बीच सभी प्रकार के टीबी से मृत्यु दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- कुल संख्या में, एचआईवी को छोड़कर टीबी के सभी रूपों से अनुमानित मौतों की कुल संख्या 2020 के लिए 4.93 लाख थी, जो 2019 के अनुमान से 13 प्रतिशत अधिक थी।

- कुपोषण, मधुमेह, एचआईवी, तंबाकू धूम्रपान और शराब जैसी सहवर्ती बीमारियां टीबी से पीड़ित व्यक्ति को पूर्वाग्रह और गंभीरता से प्रभावित करती हैं। अप्रैल 2018 से फरवरी 2022 तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के रूप में निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के तहत 57.33 लाख टीबी रोगियों को लगभग 1,488 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

**कोविड-19 महामारी और टीबी**

- कोविड-19 महामारी के प्रसार ने देश में टीबी अधिसूचनाओं की प्रक्रिया को प्रभावित किया है।
- भारत टीबी रिपोर्ट 2022 में उल्लिखित है कि क्षय रोग (टीबी) के खिलाफ लड़ाई को दशकों के अपेक्षित लाभ से कम सफलता मिली।
- राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- विदित है कि टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी 2017- 25) के अनुसार टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- अठारह राज्यों ने राज्य विशिष्ट रणनीतिक योजनाओं को औपचारिक रूप से लागू करके 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

**क्षय रोग उन्मूलन वर्ष 2017-2025 हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना**

- आरएनटीसीपी ने वर्ष 2025 तक भारत में टीबी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए 'क्षयरोग वर्ष 2017-2025' (एनएसपी) के लिए 'राष्ट्रीय रणनीतिक योजना' जारी की है।
- एनएसपी टीबी उन्मूलन के अनुसार डीटीपीबी को चार रणनीतिक स्तंभों में एकीकृत किया गया है
    1. पता लगाना (डिटेक्ट)
    2. उपचार करना (ट्रीट)
    3. रोकथाम (प्रिवेंट)
    4. निर्माण (बिल्ड)

**संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)**

- राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम (एनटीपी) की शुरूआत भारत सरकार ने वर्ष 1962 में बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार से जुड़े जिला टीबी केंद्र मॉडल के रूप में की थी।

- वर्ष 1978 में बीसीजी टीकाकरण को टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारत सरकार तथा स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एसआईडीए) ने वर्ष 1992 में एनटीपी की संयुक्त समीक्षा की थी तथा उन्हें कार्यक्रम में कुछ कमियां जैसे कि प्रबंधकीय कमजोरियां, अपर्याप्त वित्त पोषण, एक्स-रे पर अत्यधिक निर्भरता, गैर-मानक उपचार कोर्स, उपचार पूर्ण होने की दर में कमी एवं उपचार परिणामों पर सुव्यवस्थित/पद्धतिबद्ध सूचनाओं का अभाव पाया गया था।
- डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 1993 में टीबी को वैश्विक आपातकाल घोषित किया। उसने क्षय रोग की चिकित्सा के लिए प्रत्यक्ष प्रेक्षित थेरेपी, छोटा-कोर्स (डॉट्स/डाइरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स), अर्थात् सीधे तौर पर लिए जाने वाला छोटी अवधि के उपचार की स्थापना की तथा सभी देशों से इसे अपनाने की सिफ़ारिश की।
- भारत सरकार ने वर्ष 1993 में एनटीपी को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में लागू किया। डॉट्स की आधिकारिक तौर पर शुरूआत वर्ष 1997 में आरएनटीसीपी रणनीति के अंतर्गत की गयी थी तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005 के अंत तक पूरे देश को कवर किया गया था।

**निक्षय**

- टीबी अधिसूचना की सुगम्यता के लिए आरएनटीसीपी ने सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों के लिए केस-आधारित वेब-आधारित टीबी निगरानी प्रणाली विकसित की है, जिसे "निक्षय" कहा जाता है।

**निक्षय पोषण योजना**

- यह उन लोगों के लिए शुरू की गई है, जो टीबी से ग्रस्त हैं।
- इस योजना के तहत टीबी पीड़ितों को सरकार हर महीने 500 रूपये की आर्थिक सहायता देती है

**सरकारी निजी भागीदारी**

- टीबी रोकथाम एवं देखभाल तथा प्रदाताओं को सार्वजनिक-निजी (पीपीएम) टीबी मामलों की अधिसूचना, उपचार अनुपालना और उपचार की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्रदान किया जाता हैं।
- प्रोत्साहन (इंसेंटिव) लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं।

**निष्कर्ष**

फलतः बेहतर बुनियादी सुविधाओं के विकास, पोषण, जन जागरूकता अभियान के साथ योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा इसे नियंत्रण किया जा सकता है।

**स्रोत: द हिन्दू**

## भारत की सुपरकंप्यूटिंग क्षमताएं

| यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित | |
|---|---|
| **प्रारम्भिक परीक्षा** | **मुख्य परीक्षा** |
| **प्रथम प्रश्न पत्र :** राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ | **द्वितीय प्रश्न पत्र :** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |

**संदर्भ**

- सुपर-कंप्यूटर (शीर्ष 500) की वैश्विक रैंकिंग सेवा के अनुसार, भारत में 500 में से केवल 3 शीर्ष क्रम के सुपर कंप्यूटर हैं, जबकि शीर्ष 100 में भारतीय सुपर कंप्यूटर स्थान बनाने में असफल रहा है।
- विदित है कि सुपर कंप्यूटर नियमित मशीनों की तुलना में तेजी से बड़ी कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करके गणना में तेजी ला सकते हैं। साथ ही इसका उपयोग कुछ क्षेत्रों जैसे- रसायन विज्ञान, प्रोटीन फोल्डिंग, बायोमेडिसिन में व्यापक रूप से किया जा सकता है।

**विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु**

**शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर और भारतीय सुपर कंप्यूटर**

- भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, 1990 में स्थापित किया गया था।
- परम सिद्धि 5.27 PFlops का चरम प्रदर्शन प्रदान करता है, शीर्ष 500 वैश्विक रैंकिंग सेवा में इसे नवंबर 2020 में विश्व के 63वें सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में स्थान दिया गया था। उसके बाद से यह 111वें स्थान पर पहुँच गया है।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान (IITM) प्रत्यूष सुपरकंप्यूटर, जो कभी शीर्ष 100 में हुआ करता था, अब 132वें स्थान पर है।
- भारत में शीर्ष 500 की समग्र सूची में तीन सुपर कंप्यूटर हैं।

**विश्व परिदृश्य**

- विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में चीन और अमेरिका का हिस्सा लगभग दो-तिहाई है, जिसमें दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से क्रमशः 173 और 128 हैं।
- ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में 'फ्रंटियर' नामक एक नया यूएसए निर्मित सुपर कंप्यूटर इन्स्टाल किया गया है जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा।
- ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित दुनिया का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर फ्रंटियर 1,685 ने चरम प्रदर्शन किया।

**सुपरकंप्यूटर की कंप्यूटिंग क्षमता का मापन**

- सुपरकंप्यूटर की कंप्यूटिंग क्षमता को फ्लोटिंग-पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड या FLOPS में मापा जाता है।
- एक पेटाफ्लॉप्स 1,000,000,000,000,000 (एक क्वाड्रिलियन) फ्लॉप्स या एक हजार टेराफ्लॉप्स के बराबर है।
- ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित दुनिया का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर फ्रंटियर 1,685 है।

**महत्व**

- स्थानीय सुपरकंप्यूटिंग क्षमताओं का निर्माण बायोमेडिसिन, अंतरिक्ष तकनीक और जलवायु में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को मजबूत करेगा, जिसके लिए उच्च गणना शक्ति की आवश्यकता होती है।
- यद्यपि, भारतीय सुपर कंप्यूटरों की उपलब्ध कंप्यूटिंग क्षमता उनके वैश्विक समकक्षों की तुलना में काफी कम है।

**भारत और सुपरकंप्यूटिंग क्षमता**

- भारत सहित दुनिया भर के देश पिछले कुछ वर्षों में सुपरकंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं।
- इस वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने देश के विभिन्न संस्थानों में चार सुपर कंप्यूटर स्थापित किए हैं।
- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के तहत 2015 से देश में 24 पेटाफ्लॉप की कुल गणना क्षमता वाले पंद्रह सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं।

**राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम)**

- संचालन और कार्यान्वयन
    - राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- एनएसएम के चार प्रमुख स्तम्भ
    - बुनियादी ढांचा,
    - अनुप्रयोग,
    - अनुसंधान एवं विकास,
    - मानव संसाधन विकास हैं।
- परिकल्पना
    - इस मिशन की निर्माण पहुंच के तहत डिजाइन, विकास, सुपरकंप्यूटिंग प्रणालियों की तैनाती और कार्य करने की जिम्मेदारी सी-डैक को सौंपी गई है।

- मिशन की 64 से अधिक पेटाफ्लॉप्स की संचयी परिकलन क्षमता के साथ 24 सुविधाओं का निर्माण और उनकी तैनाती करने की योजना है।
- अभी तक सी-डैक ने एनएसएम चरण-1 और चरण-2 के तहत 20 से अधिक पेटाफ्लॉप्स की संचयी परिकलन क्षमता के साथ भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी, आईआईएसईआर पुणे, जेएनसीएएसआर, एनएबीआई-मोहाली और सी-डैक में 11 प्रणालियां तैनात कर दी गई हैं।
- वर्तमान में पूरे देश में एनएसएम प्रणालियों में लगभग 3600 शोधकर्ताओं द्वारा कुल 36,00,000 कम्प्यूटेशनल रोजगार सफलतापूर्वक एकत्र किए गए हैं।
- देश के विभिन्न संस्थानों में स्थापित किए गए सुपर कंप्यूटर बुनियादी ढांचे ने अनुसंधान एवं विकास समुदाय की प्रमुख उपलब्धियां, उद्देश्य तथा वैज्ञानिक और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए उत्पादों को प्राप्त करने में सहायता की है।

- सुपरकंप्यूटिंग इकोसिस्टम
  - निर्मित पहुंच के तहत सी-डैक चरणबद्ध रूप से स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन और विनिर्मित सुपर कंप्यूटरों के लिए अग्रणी है।
  - इसने कंप्यूटर सर्वर ''रुद्र'' और उच्च गति वाले इंटरकनेक्ट ''त्रिनेत्र'' को डिजाइन और विकसित किया है, जो सुपर कंप्यूटरों के लिए आवश्यक प्रमुख उप-असेंबलियां हैं।

**स्रोत: मिंट**